भारत सरकार
वत्त मंत्रालय
आ र्थक कार्य वभाग

लोक सभा
अतारां कत प्रश्न सं. 3682

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है)

शहरी खपत में मंदी

3682. डॉ. मोहम्मद जावेद:

क्या वत्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या सरकार ने शहरी खपत में मंदी के लए जिम्मेदार कारकों का आकलन कया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनका समाधान करने के लए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ख) शहरी खपत में मंदी से सबसे अ धक प्रभा वत क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और सौंदर्य प्रसाधन सेवाओं को सहायता देने के लए सरकार द्वारा क्या उपाय कए जा रहे हैं;
(ग) क्या सरकार ने खपत को बढ़ाने के लए शहरी क्षेत्रों में व्यय योग्य आय बढ़ाने के लए व शष्ट नीतियों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का मांग में वृ द्ध और खपत बढ़ाने के लए इलेक्ट्रॉनिक सामग्री पर आयकर और जीएसटी दरों में कमी करने का वचार है?

उत्तर
वत्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, शहरी क्षेत्रों के लए मौजूदा मूल्यों पर अनुमानित औसत मा सक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (व भन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से परिवारों द्वारा प्राप्त मुफ्त वस्तुओं के मूल्यों को ध्यान में रखे बिना) वर्ष 2022-23 में ₹6,459 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹6,996 हो गया। सरकार ने समग्र आ र्थक वकास को बढ़ावा देने, व्यापारिक सुगमता में सुधार करने, कौशल वकास और रोजगार सृजन के लए एक इको सस्टम को सक्षम बनाने तथा अवसंरचना और शहरी वकास को बढ़ावा देने के लए व भन्न पहलें की हैं। सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में, करदाताओं को लाभान्वित करने के लए व्यक्तिगत आयकर के स्लैब और दरों में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव कया है। इन प्रयासों से प्रयोज्य (डस्पोजेबल) आय में वृ द्ध होने की उम्मीद है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं सहित व भन्न वस्तुओं और सेवाओं की शहरी खपत को बढ़ावा मलेगा। जीएसटी दरें जीएसटी परिषद की सफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। फलहाल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कमी के लए जीएसटी परिषद द्वारा कोई सफारिश नहीं की गई है।

**** ****